सोने और चांदी खरीदारों के लिए बड़ी राहत

कीमतें करीब 74,000 रुपए तक कम हुईं

नई दिल्ली, 1 फरवरी. सोने और चांदी की कीमतों में रविवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे सोने की कीमत 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2.70 लाख रुपए प्रति किलो हो गई है.

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, चांदी की कीमत 73,599 रुपए कम होकर 2,65,751 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 3,39,350 रुपए प्रति किलो थी.

24 कैरेट सोने का दाम 17,098 रुपए कम होकर 1,48,697 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,65,795 रुपए प्रति 10 ग्राम था.

22 कैरेट सोने का दाम 1,65,131 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,36,206 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. 18 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,11,523 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,24,346 रुपए प्रति 10 ग्राम थी.

चांदी की कीमत 35.89 डॉलर प्रति औंस या 31.37 प्रतिशत कम होकर 78.531 डॉलर प्रति औंस हो गई है. जानकारों के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट के पीछे कई कारक हैं. इसमें अमेरिकी डॉलर का मजबूत होने, फेड की ओर से ब्याज दरों को जनवरी में स्थिर और अमेरिकी फेड प्रमुख का बदलना शामिल है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 2 अप्रैल 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1,48,104 रुपए और चांदी के 05 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 2,65,652 रुपए था.

बजट के चलते कमोडिटी मार्केट में रविवार को स्पेशल सेशन रखा गया था, जिस कारण आज सोने और चांदी की नई कीमतें अपडेट हुई हैं.

रविवार के कारण अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट बंद है. इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली थी. इस दौरान कॉमेक्स पर सोने की कीमत 609.70 डॉलर प्रति औंस या 11.39 प्रतिशत कम होकर 4,745.10 डॉलर प्रति औंस हो गई है.

वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर महंगा

नयी दिल्ली, 01 फरवरी. तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी की है जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में रविवार से 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर 1,740.50 रुपये का हो गया है. यह मई 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है. जनवरी में इसकी कीमत 111 रुपये बढ़ाकर 1,691.50 रुपये की गयी थी.

पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने वाला बजट

अनिल अग्रवाल ने विकास को ध्यान में रखने वाला बजट बताया

नयी दिल्ली, 01 फरवरी. वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने रविवार को कहा कि विकास को ध्यान में रखते हुए पेश किये गये केंद्रीय बजट में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और विनिर्माण को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है.

उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं की आजीविका में सुधार, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और मेडिकल टूरिज़्म जैसे रोज़गार-गहन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम प्रावधान किये गये हैं.

उन्होंने बजट में महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ धातुओं पर सरकार के विशेष ध्यान का स्वागत किया. अग्रवाल ने कहा कि यह पहल ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान एवं विकास और मैन्युफैक्चरिंग के नये अवसर खोलेगी. इससे न केवल इस क्षेत्र में विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की मिनरल सुरक्षा भी मजबूत होगी.

अग्रवाल ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में दी गयी छूट को भी लाभकारी कदम बताया गया है, जिससे घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी.

अग्रवाल ने कहा, 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ैड) में लचीलेपन की घोषणा भी एक अच्छा कदम है, जिससे घरेलू बाज़ार में बिक्री बढ़ेगी. मैं प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को बधाई देना चाहूंगा, जो अनिश्चितत समय के बीच भी अर्थव्यवस्था को स्थिरता से चला रहे हैं.'

बजट के बाद 2,370 अंक लुढ़का सेंसेक्स

मुंबई, 01 फरवरी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में रविवार को विशेष सत्र के दौरान बड़ी गिरावट देखी गयी.

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 2,826 अंक के उतार-चढ़ाव के बाद अंत में 1,546.84 अंक (1.88 प्रतिशत) टूटकर 80,722.94 अंक पर बंद हुआ जो 30 सितंबर 2025 के बाद का निचला स्तर है.

बाजार बजट से पहले तेजी में था और एक समय सेंसेक्स 456 अंक चढ़कर 82,726.65 अंक पर पहुंच गया था. लेकिन वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त होते-होते सूचकांक तेजी से गिर गया. कुछ ही देर में यह 2,370 अंक गिरकर 79,899 अंक तक उतर गया था जो बीच कारोबार में गत 01 सितंबर के बाद का निचला स्तर है.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 495.20 अंक यानी 1.96 प्रतिशत की गिरावट में 30 सितंबर के बाद के निचले स्तर 24,825.45 अंक पर बंद हुआ. यह इसका भी पिछले साल 03 सितंबर महीने का निचला स्तर है. सूचकांक ऊपर 25,440.90 अंक और नीचे 24,571.75 अंक तक गया.

चौतरफा बिकवाली के बीच मझौली और छोटी कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ा. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 2.06 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 2.73 प्रतिशत गिर गया.

एनएसई में आईटी सूचकांक की 0.57 प्रतिशत की तेजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर गिरावट में रहे.

जनवरी में सकल जीएसटी संग्रह 1,93,384 करोड़ रुपये पर

नयी दिल्ली, 01 फरवरी. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जनवरी में सकल राजस्व संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़कर 1,93,384 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पिछले साल जनवरी में यह आंकड़ा 1,82,094 करोड रुपये रहा था. सूत्रों ने बताया कि जनवरी में घरेलू जीएसटी राजस्व 4.8 प्रतिशत बढ़कर 1,41,32 करोड़ रुपये पर रहा. वहीं आयात पर कर से प्राप्त राजस्व 10.1 प्रतिशत बढ़कर 52,253 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. कुल रिफंड में जनवरी 2025 की तुलना में 3.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी और यह 22,665 करोड़ रुपये रहा. इस प्रकार शुद्ध जीएसटी संग्रह 7.6 फीसदी बढ़कर 1,70,719 करोड़ रुपये रहा.

बजट 2026-27 ऐतिहासिक और अभूतपूर्व : शिवराज

यह बजट समाज की समृद्धि तथा संकल्पों की सिद्धि का बजट है

यह 2047 के आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत की नींव रखता है

नई दिल्ली, 1 फरवरी 2026: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने वाला ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बजट बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने का महाकाव्य है और समाज की समृद्धि तथा संकल्पों की सिद्धि का बजट है. यह डेवलप्ड इंडिया का डायनामिक बजट है, जो वर्ष 2047 के आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत की नींव रखता है.

ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 21% वृद्धि की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का सम्मिलित बजट अब 4,35,779 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है.

'विकसित भारत जी राम जी' योजना के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है. मनरेगा के लिए केंद्र का बजट 95,692 करोड़ रुपये रखा गया है, जो राज्यों के हिस्से सहित 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा.

श्री चौहान ने बताया कि यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला—इन सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने लखपति दीदी योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए 'स्॥श्व-मार्ट' के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात कही. इसके तहत हर जिले में स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बेचने के लिए कम्युनिटी-ओन्ड रिटेल आउटलेट बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण महिलाएं आजीविका से आगे बढ़कर उद्यमिता की ओर बढ़ सकेंगी.

पंचायतों को सीधे मिलने वाली राशि भी दोगुनी कर 55,900 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्राम विकास को नई गति मिलेगी. कृषि बजट 1.32 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है.

शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देते हुए नारियल, कोको, काजू, चंदन और फल-सब्जी पर विशेष प्रावधानों की बात कही. उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबी दूर करने, किसानों की आय बढ़ाने और विकसित, स्वावलंबी तथा रोजगारयुक्त गांव के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

विमान ईंधन एक प्रतिशत सस्ता

नयी दिल्ली, 1 फरवरी. घरेलू विमान सेवा कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए तेल विपणन कंपनियों ने विमान ईंधन की कीमतों में लगभग एक प्रतिशत की कटौती की है. यह लगातार दूसरा महीना है जब देश में विमान ईंधन की कीमत कम हुई है. इससे पहले 1 जनवरी से यह करीब सात प्रतिशत सस्ता हुआ था.

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार से दिल्ली में विमान ईंधन का मूल्य 929.63 रुपये (1.01 प्रतिशत) घटकर 91,393 रुपये प्रति किलोलीटर रह गया है. इससे पहले जनवरी में इसकी कीमत 7.38 प्रतिशत कम हुई थी.

कोलकाता में यह 932 रुपये (0.98 प्रतिशत) सस्ता होकर 94,446 रुपये प्रति किलोलीटर और मुंबई में 878 रुपये (1.02 प्रतिशत) सस्ता होकर 85,475 रुपये प्रति किलोलीटर का हो गया है.

यूपीआई ट्रांजैक्शन में 28 प्र. की बढ़ोतरी

जनवरी में कुल 21.70 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए

नई दिल्ली, 1 फरवरी. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए जनवरी में ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जनवरी में कुल 21.70 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए. इसके साथ ही ट्रांजैक्शन की कुल राशि में भी 21 प्रतिशत की सालाना बढ़त के साथ यह 28.33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई.

रविवार को जारी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है.

एनपीसीआई के मुताबिक, महीने के हिसाब से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या और रकम में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है. जनवरी में यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ता रहा.

जनवरी महीने में रोजाना औसतन 91,403 करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ, जो दिसंबर के 90,217 करोड़ रुपए के मुकाबले ज्यादा है.

जनवरी में रोजाना औसतन 70 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 69.8 करोड़ था.

एफएंडओ पर एसटीटी बढ़ी, बाजार धड़ाम

नई दिल्ली, 1 फरवरी. केंद्र सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बढ़ती सट्टेबाजी और उससे जुड़े प्रणालीगत जोखिमों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है. राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव के अनुसार, एसटीटी में वृद्धि का मकसद अत्यधिक सट्टा गतिविधियों पर लगाम लगाना और बाजार में स्थिरता बनाए रखना है. बजट 2026 के तहत फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत और ऑप्शंस पर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.

भारत के विकास का अगला चरण पूंजी-समर्थित : सिंह

नयी दिल्ली, 01 फरवरी. पीबी फिनटेक के जॉइंट ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सरबवीर सिंह ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट राजकोषीय अनुशासन पर आधारित है और यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत के विकास का अगला चरण पूंजी-समर्थित तथा सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम प्रेरित होगा.

उन्होंने कहा कि बजट में मजबूत संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ जन-केंद्रित दृष्टिकोण भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है.

सिंह के अनुसार, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का निरंतर प्रयास बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए मजबूत तथा पूर्वानुमेय मांग की पाइपलाइन तैयार करेगा.

समाचार विशेष

तेजस्वी की कद के साथ जवाबदेही बढ़ी

परिवारवाद से लेकर पार्टी बचाने तक क्या हैं चुनौतियां?

पटना. राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्य जितना परेशान होना था हो चुका है, अब सत्य की विजय का समय शुरू होगा. इस एक पंक्ति में आत्मविश्वास भी झलकता है और राजनीतिक चुनौती का संकेत भी. लालू प्रसाद यादव के बाद अब पार्टी की पूरी कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आ गई है. यह ताजपोशी जितनी स्वाभाविक दिखती है, उतनी ही कठिन भी है, क्योंकि अब हर जीत, हर हार और हर फैसले की सीधी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर ही होगी.

राजद में पहले भी नेतृत्व परिवार के भीतर सौंपा गया है, लेकिन यह पहला मौका है जब लालू प्रसाद यादव की छाया लगभग पूरी तरह हट चुकी है. अब संगठन, रणनीति, गठबंधन और चुनावी फैसलों में अंतिम निर्णय तेजस्वी यादव का होगा. इसका मतलब साफ है कि किसी भी हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आएगी. अब यह कहना आसान नहीं रहेगा कि फैसले ऊपर से हुए या हालात मजबूरी के थे.

तेजस्वी यादव की पोस्ट से संकेत मिलता है कि वे आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाने के मूड में हैं. वे गांधी, लोहिया और अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हैं, जिससे साफ है कि वे खुद को गरीबों और पिछड़ों की आवाज के रूप में पेश करना चाहते हैं. हालांकि इसके साथ उनकी चुनौतियां भी कई गुना बढ़ गई हैं. यह समय सिर्फ विरोध की राजनीति का नहीं, बल्कि भरोसा कायम करने का भी है.

पार्टी के भीतर असंतोष और टूट का खतरा

तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव से जुड़े विवादों ने साफ कर दिया है कि राजद का पारिवारिक संकट अब सार्वजनिक हो चुका है. रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं, वहीं मीसा भारती को भी इस पद की उम्मीद थी. लालू परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं, ऐसे में यह अंदरूनी कलह पार्टी की एकता को नुकसान पहुंचा सकती है. तेजस्वी के लिए परिवार को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी.

कैसे खत्म होगा कांग्रेस का विवाद

नई दिल्ली. राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं को बहुत सख्त संदेश दिया है. दिल्ली में पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आलाकमान की ओर से कहा गया कि नेता आपस में लड़ना बंद करें.

यह भी कहा गया कि जाति और धर्म का मामला उठा कर पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी और अकाली दल को मजबूत कर रहे हैं. उसके बाद से शांति बहाली हो गई है. लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है. असल में पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं. फरवरी में चुनाव होगा. उससे पहले कांग्रेस के नेता अभी से नेतृत्व का मुद्दा सुलझाने में लग गए हैं. इसी वजह से दलित बनाम जाट का विवाद भी शुरू हुआ है. गौरतलब है कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था. दलित सीएम बनाने का यह दांव कामयाब नहीं हुआ लेकिन चन्नी को कांग्रेस ने एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर स्थापित कर दिया है.

अब चरणजीत सिंह चन्नी अपने को नेतृत्व का स्वाभाविक दावेदार मान रहे हैं. वे लोकसभा का चुनाव जीत गए और कृषि मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं.

नीतीश के यहां वापसी चाहते हैं पीके, आरसीपी

पटना. बिहार में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की आहट सुनाई दे रही है. एक तरफ इस बात की चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार ने इतनी ठंड में समृद्धि यात्रा सिर्फ भाजपा को यह दिखाने के लिए निकाली कि वे पूरी तरह से फिट हैं. तो दूसरी ओर नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कर भाजपा ने अपने बिहार प्लान की रूपरेखा जाहिर की है. भाजपा को इसी विधानसभा में अपना मुख्यमंत्री बनाना है. सवाल सिर्फ टाइमिंग का है.

भाजपा की योजना के मुताबिक अगर वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसी तरह से जीत जाती है तो उसके बाद बिहार में बदलाव हो सकता है. अगर पश्चिम बंगाल में वह नहीं जीतती है तो अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक इंतजार किया जाएगा. नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के अंदर कई खेमे बन गए हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं लेकिन हर खेमे में इस बात पर सहमति है कि सत्ता हाथ से नहीं जाने देनी है. यानी भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है.

इस वजह से दोनों बड़ी पार्टियों में गहरा अविश्वास बना है और इसके बीच कई नेता घर वापसी के लिए बेकरार हैं. सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर वापसी करना चाहते हैं. जानकार सूत्रों का कहना है कि वे अपनी पार्टी का विलय जनता दल यू में करने के लिए तैयार हैं. नीतीश कुमार के करीबी सलाहकार रहे उदयकांत मिश्रा के जरिए बातचीत शुरू हुई थी. लेकिन जब उदयकांत मिश्र ने प्रशांत किशोर की मुलाकात नीतीश से कराने का प्रयास किया तब तक बात लीक हो गई और पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस मुलाकात को रोक दिया. बताया जा रहा है कि इसके बाद पार्टी के बड़े नेता की इसमें एंट्री हुई. वे साये की तरह नीतीश कुमार के साथ रहते हैं. उनके जरिए भी बात हुई है.

वे और मुख्यमंत्री अलग अलग नहीं

बहरहाल, प्रशांत किशोर के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की वापसी की भी चर्चा है. जानकार सूत्रों का कहना है कि उनकी भी चर्चा प्रशांत किशोर के साथ ही शुरू हुई थी. ध्यान रहे वे अभी पीके की पार्टी जन सुराज में ही हैं. लेकिन उन्होंने अलग से बयान दे दिया कि वे और मुख्यमंत्री अलग अलग नहीं हैं. इसके बाद ललन सिंह ने कहा कि आरपीसी पार्टी को 72 से 42 सीट पर ले आए थे. पार्टी में उनके लिए जगह नहीं है. लेकिन इसके बाद भी 24 जनवरी को ललन सिंह का जन्मदिन आया तो आरसीपी ने सोशल मीडिया में उनको खुले दिल से बधाई दी.

विशेष — उनके हाल ही के भाषण सोशल मीडिया पर सुर्खियों में

बयानों को लेकर फिर चर्चाओं में वसुंधरा

जयपुर. राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक निर्णायक भूमिका निभा चुकीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं. नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी की राजनीति में वसुंधरा राजे के सियासी भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं.

हालांकि बीते कुछ समय से राजे के बयानों में सीधा टकराव नहीं, बल्कि संकेतों की राजनीति दिखाई दे रही है. वह न तो खुलकर किसी भूमिका की घोषणा कर रही हैं और न ही सक्रिय विरोध की राह पर हैं, लेकिन उनके वक्तव्य यह साफ करते हैं कि वह हाशिये पर रहने को तैयार नहीं हैं. पार्टी के भीतर और बाहर, उनके शब्दों को गंभीरता से लिया जा रहा है.

राजनीति में दिल टूटते हैं और भावनाएं आहत होती हैं हालिया दो सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंच से उनके भाषण सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते नजर आए. राजे ने महिलाओं की राजनीति में स्थिति और सार्वजनिक जीवन की जटिलताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीति में टिके रहने के लिए पुरुषों से तीन गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में दिल टूटते हैं और भावनाएं आहत होती हैं. राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी के तौर पर नहीं बल्कि कुछ गहरे राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं. जयपुर में आयोजित जाट महिला शक्ति संगम को संबोधित करते हुए राजे ने कहा कि राजनीति में महिलाओं को स्वीकार्यता और पहचान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. योग्यता और समर्पण के बावजूद महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक प्रयास करने पड़ते हैं. उनके इस बयान को राजनीति में महिलाओं के सामने मौजूद संरचनात्मक चुनौतियों पर सीधी टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है. इसी तरह दूसरी टिप्पणी राजे ने डीडवाना-कुचामन जिले की छोटी खाटू में आयोजित आचार्य महाश्रमण मर्यादा महोत्सव में एक धार्मिक मंच से बोलते हुए की. राजे ने अहिंसा की अवधारणा को राजनीति से जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है और किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना हिंसा है.

आंतरिक समीकरणों और सत्ता संघर्षों की ओर इशारा

हालांकि यह बयान एक धार्मिक कार्यक्रम में दिया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके निहितार्थ राजनीतिक हैं. जानकारों के अनुसार, भावनात्मक चोट और टूटे भरोसे का उनका बार-बार उल्लेख आंतरिक राजनीतिक समीकरणों और सत्ता संघर्षों की ओर इशारा करता है. बीते कुछ महीनों से वसुन्धरा राजे के बयानों में एक सूक्ष्मता और अप्रत्यक्षता देखी जा रही है, जो कई तरह की राजनीतिक व्याख्याओं को जन्म दे रही है. राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष गोधा ने कहा कि दो बार मुख्यमंत्री रह चुकीं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में लंबे समय तक सक्रिय रहीं वसुन्धरा राजे राजनीति की कठोर वास्तविकताओं से भली-भांति परिचित हैं.